Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 201-2015] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015 (AGRAHAYANA 9, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 30th November, 2015

No. 21-HLA of 2015/90.— Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment and Validation) Bill,2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 21- HLA of 2015.

INDIRA GANDHI UNIVERSITY, MEERPUR (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2015

A

BILL

further to amend Indira Gandhi University, Meerpur, Act, 2013.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment and Validation) Act, 2015.

Amendment of Section 1 of Haryana Act 29 of 2013.

2. Sub-section (2) of section 1 of Indira Gandhi University, Meerpur, Act, 2013 (hereinafter called the principal Act), shall be omitted.

Validation.

3. Notwithstanding notification under sub-section (2) of section 1 of the principal Act having not been issued, anything done or any action taken or purported to have been done or taken during the period commencing from the 26th November, 2013 under the provisions of the principal Act to the commencement of this amending Act, shall, for all purposes, be deemed to be, and to have always been done and taken in accordance with law and shall not be called in question before any court of law on this ground.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Since there has already been a well established Post Graduate Regional Centre of MDU, Rohtak functioning at Meerpur with all the requirement of adequate land, building, staff, budget provision and sufficient number of Post-Graduate courses, the State Government upgraded this Regional Centre as Indira Gandhi University, Meerpur by enacting the Indira Gandhi University, Meerpur Act, 2013.

However in the Principal Act, the provisions for validation could not be included. Hence the validation clause has to be incorporated in the Act, and this Act may be called Indira Gandhi University, Meerpur (Amendment and Validation) Act, 2015. The proposed provisions are necessary for the smooth functioning of the University.

Hence, this Bill.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 30th November, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2015 dk fo/k;d l[;k 21–,p-,y-,-

bfUnjk xk/kh fo'ofo|ky;] ehjiqj ¼l'kks/ku rFkk fof/kekU;dj.k½ fo/k;d] 2015

bfUnjk xk/kh fo'ofo|ky;] ehjiqj vf/kfu;e] 2013]

dk vkxs l'kks/ku

djus ds fy,

fo/k;d

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1- यह अधिनियम इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संषोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015] कहा जा सकता है।

2013 का हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 1 का संषोधन।

2- इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर अधिनियम, 2013 (जिसे, इसमें, इसके बाद] मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप–धारा (2)का लोप कर दिया जायेगा ।

विधिमान्यकरण ।

3- मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी नहीं होते हुए भी, इस संशोधित अधिनियम के प्रारम्भ से मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 2013 से प्रारम्भ अवधि के दौरान की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार की गई, तथा सदैव की गई बात तथा कार्रवाई समझी जाएगी तथा इस आधार पर किसी विधि न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं होगी ।

mnns';kas rFkk dkj.kksa dk fooj.k

चूंकि, मीरपुर में पहले से ही स्थापित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक का स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र चल रहा है जो कि पर्याप्त भूमि, भवन, स्टाफ, बजट प्रावधान तथा पर्याप्त मात्रा में स्नातकोत्तर कोर्सिस की मांग को पूरा कर रहा है, राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर अधिनियम, 2013 को अधिनियमित करके इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया।

तथापि मूल अधिनियम में सत्यापन के लिए प्रावधानों को शामिल नहीं किया जा सका था। अतः सत्यापन खंड अधिनियम में सम्मिलित किया जाना है तथा, यह अधिनियम इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015 कहा जा सकता है। प्रस्तावित प्रावधान विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

राम बिलास षर्मा,
षिक्षा मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 30 नवम्बर, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।